1800 पन्नों की चार्जशीट दायर की है मुंबई पुलिस ने जूनियर डॉक्टर पायल तड़वी की खुदकशी मामले में। इस मामले में तीनों आरोपित डॉक्टरों हेमा आहूजा, भक्ति मेहरे और अंकिता खंडेलवाल को 29 मई को गिरफ्तार किया गया था। तब से तीनों न्यायिक हिरासत में हैं।

दुरुस्त सेहत के साथ सही रास्ते पर बढ़ रहा चंद्रयान-2

सोमवार को दोपहर 2 :43 बजे श्रीहरिकोटा से भरी थी उड़ान, अहम पड़ावों के बाद अभियान के अपडेट जारी करेगा इसरो

बेंगलुरु, प्रेट्र : 'बाहुबली' के कंधों पर सवार होकर चांद की ओर कूच करने वाले चंद्रयान-2 की सेहत दुरुस्त है और यह बिलकुल सही रास्ते पर बढ़ रहा है। देश के दूसरे चंद्र अभियान की रवानगी के दूसरे दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सोमवार को दोपहर 2:43 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के सबसे बड़े रॉकेट जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्हीकल-मार्क 3 (जीएसएलवी-एमके3) ने चंद्रयान-2 को लेकर उड़ान भरी थी। उड़ान के 16 मिनट 23 सेकंड बाद रॉकेट ने यान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया था।

इसरो के बेंगलुरु स्थित मुख्यालय के एक अधिकारी ने बताया, 'यान की सेहत दुरुस्त है। अभियान के बारे में कोई आधिकारिक अपडेट नहीं जारी किया गया है, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। कुछ छोटे पड़ाव हैं, जिनके बारे में सही वक्त आने पर जानकारी दी जाएगी।' चंद्रयान-2 के तीन हिस्से हैं- ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान।

ऑर्बिटर सालभर चांद की परिक्रमा करते हुए प्रयोगों को अंजाम देगा। वहीं लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरकर प्रयोग करेंगे। सात सितंबर को चांद पर लैंडर-रोवर की लैंडिंग के साथ ही भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद पर अपना यान उतारा है।

2008 में भारत ने चंद्रयान-1 भेजा था। यह ऑर्बिटर मिशन था, जिसने 10 महीने तक चांद की परिक्रमा करते हुए प्रयोगों को अंजाम दिया था। चांद पर पानी की खोज का श्रेय इसी अभियान को जाता है। चंद्रयान-2 इसी खोज को आगे बढ़ाते हुए वहां पानी और अन्य खनिजों के प्रमाण जुटाएगा। चंद्रयान-2 इसलिए भी खास है, क्योंकि इसके लैंडर-रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव के जिस हिस्से पर उतरेंगे, अब तक वहां किसी देश का यान नहीं उतरा है। चांद के इस हिस्से पर पृथ्वी और हमारे सौरमंडल के विकासक्रम से जुड़े कई राज छिपे होने की उम्मीद है।

गोदरेज और एलएंडटी जैसी निजी कंपनियों का भी रहा योगदान

मुंबई, प्रेट्र : भारत की शान बढ़ाने रवाना हुए चंद्रयान-2 की सफलता में गोदरेज समूह और लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) जैसी कई निजी कंपनियों की भी अहम भूमिका रही। इन कंपनियों ने हार्डवेयर से लेकर कई अन्य क्षेत्रों में अभियान को सहयोग दिया। इन दोनों बड़े समूहों के अतिरिक्त अनंत टेक्नोलॉजीज, एमटीएआर टेक्नोलॉजीज, आइनॉक्स टेक्नोलॉजीज, लक्ष्मी मशीन वर्क्स, सेंटम अवसरल और कर्नाटक हाइब्रिड माइक्रोडिवाइसेज जैसी छोटी निजी कंपनियों की भी अभियान में भूमिका रही।

गोदरेज एयरोस्पेस के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट और कारोबारी प्रमुख एसएम वैद्य ने कहा, 'कंपनी ने जीएसएलवी एमके 3 रॉकेट के लिए एल110 इंजन और सीई20 इंजन मुहैया कराए थे। कंपनी ने ऑर्बिटर व लैंडर के लिए थ्रस्टर और डीएसएन एंटीना के लिए कुछ उपकरण भी तैयार किए थे।' एलएंडटी डिफेंस के सीनियर एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट और पूर्णकालिक निदेशक जेडी पाटिल ने कहा कि उड़ान के लिए कुछ जरूरी हार्डवेयर और अन्य उपकरण मुहैया कराते हुए कंपनी ने अभियान में अपना योगदान दिया। हार्डवेयर के अलावा एस-200 सॉलिड बूस्टर्स की टेस्टिंग में भी कंपनी ने भूमिका निभाई थी। पाटिल ने बताया कि एलएंडटी ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। कंपनी इसरो के सभी श्रेणी के रॉकेटों एसएलवी3, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी-एमके3 से जुड़ी रही है।

सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) ने अभियान के लिए स्पेशल क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील की आपूर्ति की थी। यह स्टील सेलम के स्टील प्लांट से सप्लाई किया गया।

23 'स्वयंभू' विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने से बचें छात्र : यूजीसी

नई दिल्ली, प्रेट्र : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यूजीसी एक्ट का उल्लंघन कर संचालित हो रहे 23 'स्वयंभू' और 'गैरमान्यता प्राप्त' विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। आयोग ने छात्रों को इन संस्थानों में प्रवेश लेने के प्रति चेताया है।

यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने उपरोक्त जानकारी दी है। इन विश्वविद्यालयों में सर्वाधिक आठ उत्तर प्रदेश में और सात दिल्ली में हैं। उन्होंने बताया कि लखनऊ स्थित भारतीय शिक्षा परिषद का मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश: वरानस्य संस्कृत विश्वविद्यालय (वाराणसी), गांधी हिंदी विद्यापीठ (वाराणसी), महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय (प्रयागराज), नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी (कानपुर), नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनीवर्सिटी (अलीगढ़), उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (मथुरा), महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय (प्रतापगढ़), इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद (नोएडा)।

दिल्ली : कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, वोकेशनल यूनिवर्सिटी, एडीआर- सेंट्रिक ज्यूरीडिकल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी।

सर्वाधिक आठ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश और सात दिल्ली के

यूजीसी का दफ्तर फाइल फोटो

बंगाल : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च।

ओडिशा : नबभारत शिक्षा परिषद, नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी।

अन्य : बडगानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसायटी (कर्नाटक), सेंट जॉन यूनिवर्सिटी (केरल), राजा अरबी यूनिवर्सिटी (महाराष्ट्र), श्री बोधि अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन (पुडुचेरी)।

सोनभद्र की खूनी जमीन के मूल दस्तावेज गायब

लापरवाही ▶ जमीन सोसाइटी के नाम करने संबंधी आदेश के अभिलेख लापता

उभ्भा गांव में 639 बीघा जमीन 1955 में की गई थी सोसाइटी के नाम

जागरण संवाददाता, सोनभद्र

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र स्थित उभ्भा गांव की जिस जमीन को लेकर दस लोगों को मौत के घाट उतारा गया और 28 घायल हुए, उससे जुड़े मूल दस्तावेज गायब हैं। दरअसल, भूमि सोसाइटी के नाम करने का तहसीलदार का आदेश नहीं मिल रहा है। हालांकि जांच जारी है।

नरसंहार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में भूमि से जुड़े मामलों की जांच का आदेश दिया है। इसके बाद घोरावल तहसील व मूर्तिया ग्राम पंचायत की 1995 से अब तक के भूमि मामले की जांच शुरू हो गई है। शासन ने उभ्भा गांव की 639 बीघा जमीन के साथ सभी पत्रावलियों को तलब किया तो पता चला कि 17 दिसंबर 1955 को बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी महेश्वरी प्रसाद नारायण सिन्हा ने जिस भूमि को आदर्श कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर उसके नाम कराई, उसके लिए किए गए तहसीलदार के आदेश की पत्रावली ही गायब है।

जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल से इस बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि 1955 में सोनभद्र जिला नहीं था। उस समय राबर्ट्सगंज तहसील थी। जिसका मुख्यालय मीरजापुर रहा। 1989 में जब जिला सोनभद्र बना तो वहां से अभिलेख जिले में आए लेकिन जो अभिलेख हैं उनमें तहसीलदार ने किस आदेश व नियम के तहत उभ्भा गांव की 639 बीघा जमीन आदर्श कोआपरेटिव सोसाइटी के नाम की, वह आदेश ही नहीं है। जमीन के सोसाइटी के नाम दर्ज होने सहित अन्य सभी कागजात मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब 1955 से विवाद चल रहा था तो इसकी जांच क्यों नहीं की गई? जमीन के बैनामे व दाखिल खारिज के समय भी आपत्ति लगी थी। लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा इस पर ध्यान न देकर 639 बीघे जमीन में से 148 बीघा जमीन प्रधान के नाम बैनामा होने के बाद दाखिल खारिज में उसके नाम भी चढ़ा दिया गया। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता नित्यानंद द्विवेदी ने बताया कि इस संबंध में जब आदेश की पत्रावली मांगी गई तो राजस्व विभाग सोनभद्र द्वारा लिखकर दिया गया कि पत्रावली यहां नहीं है।

> जमीन को सोसाइटी के नाम करने के तहसीलदार के आदेश की कापी नहीं मिल रही है। बाकि सभी कागजात हैं। उन्हें जांच के लिए शासन को भेज दिया गया है। इस संबंध में उच्च अधिकरियों को जानकारी दे दी गई है।
>
> **-अंकित अग्रवाल, जिलाधिकारी सोनभद्र**

अब सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 80 अंक लिखित और 20 अंक प्रैक्टिकल के

जासं, नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अगले साल से बड़ा बदलाव करने जा रहा है। 2020 से सभी विषयों के प्रश्न पत्र (लिखित परीक्षा) 80 अंक के होंगे और प्रैक्टिकल यानी आंतरिक मूल्यांकन (इंटरनल असेसमेंट) 20 अंकों का होगा। अभी तक 12वीं के केमिस्ट्री समेत कुछ ही विषयों के प्रश्न पत्र 80 अंक के थे। 12वीं में ऑब्जेक्टिव सवाल भी ज्यादा पूछे जाएंगे, जोकि एक-एक अंक के होंगे। साथ ही 10वीं में भी लिखित परीक्षा 80 अंकों की और प्रैक्टिकल 20 अंकों का होगा।

दैनिक जागरण से बातचीत में सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने बताया कि हम इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इसकी सूचना लोगों को दी जाएगी। 12वीं के सभी विषयों में यह बदलाव होगा। अब तक कुछ ही विषयों में 80 अंक के प्रश्न पत्र आते थे। बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। 12वीं के छात्र इसके लिए तैयार हो सकें, इसलिए सितंबर तक नए नियमों की जानकारी और सैंपल पेपर बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। बोर्ड प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव करने जा रहा है। मूल्यांकनकर्ताओं को पहले की तुलना में कम उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

बिहार में बारिश ने फिर डराया बाढ़ प्रभावित इलाके सहमे

जागरण टीम, पटना

मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के अग्रोपट्टी गांव में ग्रामीणों द्वारा बनाया गया चचरी पुल। जागरण

उत्तर बिहार में मंगलवार को फिर शुरू हुई बारिश ने नदियों को फिर भयावह बनाना शुरू कर दिया है। जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही। नेपाल में भी पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। कोसी-सीमांचल क्षेत्र में भी नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। इससे बाढ़ वाले इलाके में भय का माहौल है। मौसम विभाग ने फिर लगातार बारिश की भविष्यवाणी की है। आशंका है कि कोसी, महानंदा और गंडक का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा। पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और दरभंगा में नए इलाके डूबने लगे हैं। नदियों में डूबने से सात लोगों की मौत हो गई। बारिश के दौरान दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई।

उत्तर बिहार के लिए अलर्ट जारी : लगातार भारी बारिश की भविष्यवाणी के मद्देनजर पश्चिम चंपारण, मधुबनी और सीतामढ़ी में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि शुरू हो गई है। सीतामढ़ी से सटे नेपाल के रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोतरी, बारा और परसा जिले में बागमती समेत दर्जनभर नदियों के उफान के बाद बाढ़ का पानी फैल रहा है। शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 42 सेंटीमीटर ऊपर है।

नेपाल की बारिश से कोसी-सीमांचल में फिर दहशत : पहाड़ पर हो रही बारिश के कारण कमला और बागमती में भी उफान की आशंका जताई गई है। नेपाल में अगले दो दिन भारी बारिश होने की संभावना है। 26 और 27 जुलाई को सामान्य से अधिक बारिश होगी।

आज से गिराएंगे खाद्य सामग्री के पैकेट : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि बुधवार से सेना के दो हेलीकाप्टर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री के पैकेट गिराएंगे। मंगलवार को एक हेलीकाप्टर ने यह काम किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस बड़ी आपदा से निपटेगी।

26 तक मानसून रहेगा सक्रिय : बिहार में बुधवार को बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 26 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा और तापमान में गिरावट आने से गर्मी से राहत मिलेगी।

बीमार बच्चे की तड़प न देख सकी मां, चौथी मंजिल से फेंका

जागरण संवाददाता, लखनऊ

एक मजबूर मां की बेबसी ने मंगलवार को लखनऊ स्थित किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) की दीवारों तक को दहला दिया। यहां के ट्रामा सेंटर में अपने तीन माह के इकलौते बेटे की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आई यह मां उसकी तड़प देखकर कलप उठी और उसे चौथी मंजिल की खिड़की से नीचे फेंक दिया। इतनी ऊंचाई से गिरने पर मासूम की सांसें थम गईं। घटना के बाद जितने मुंह उतनी कहानी। मां का यह कदम भले ही बेबसी की वजह से उठा मगर, कानून की नजर में गंभीर अपराध ही था। लिहाजा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

कुशीनगर, उप्र के कसया स्थित धुरिया गांव के राजन सिंह की पत्नी शांति देवी ने 23 अप्रैल को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चे को जन्म दिया था। समय से पहले पैदा हुआ यह बच्चा काफी कमजोर था। एक माह तक बीआरडी में इलाज कराने के बाद भी जब मासूम की हालत में सुधार नहीं हुआ तो शांति पति और देवर अमरनाथ के साथ 26 मई को ट्रामा सेंटर पहुंची। डॉक्टरों ने मासूम को नियोनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट (एनआइसीयू) में भर्ती कर लिया। बच्चे को पीलिया, दिमागी संक्रमण सहित लिवर संबंधी समस्या थी। इसकी जानकारी डॉक्टरों ने शांति और उसके पति को दे दी थी।

गंभीर रूप से बीमार था तीन माह का इकलौता बेटा

मंगलवार सुबह करीब पांच बजे शांति एनआइसीयू यूनिट से रोते हुए निकली और शोर मचाया कि उसका बच्चा चोरी हो गया है। स्टाफ ने छानबीन की तो शांति पर ही शक हुआ। सीसी फुटेज में शांति दो मिनट के लिए बाथरूम में जाते दिखी, लेकिन इस दौरान कोई भी व्यक्ति आता-जाता नजर नहीं आया। शांति से पूछताछ की गई तो वह पति और देवर के पास चली गई। शांति ने दोनों को बताया कि उसने केएमसी यूनिट की खिड़की से बेटे को नीचे फेंक दिया है। अमरनाथ ने इसकी जानकारी ट्रामा सेंटर के डॉक्टरों को दी। सभी दौड़ते हुए नीचे पहुंचे, जहां मासूम लहूलुहान पड़ा था। उसे एनआइसीयू लाया गया, लेकिन सिर फट जाने के कारण वह दम तोड़ चुका था। एएसपी पश्चिम विकास चंद्र त्रिपाठी के मुताबिक पति की तहरीर पर शांति के खिलाफ हत्या की एफआइआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

मध्य प्रदेश में दबंगों ने मारपीट की तो महिला ने किया आत्मदाह

नईदुनिया, सतना : मध्य प्रदेश के सतना जिले के गिंजौरा गांव में एक आदिवासी महिला अनुराधा अहिरवार ने खुद को आग लगा ली। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। दबंगों ने महिला से जमीन के विवाद में मारपीट की थी। इसके बाद उसने आत्मघाती कदम उठा लिया।

सोमवार रात हुई घटना के बाद महिला को जिंदा जलाने की अफवाह उड़ गई। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल और एसडीएम संस्कृति शर्मा ने गांव पहुंचकर पूछताछ की। अनुराधा के बच्चों से पूछताछ में पता चला कि जमीन विवाद और हाथापाई के बाद उनकी मां ने खुद को आग के हवाले कर लिया था। बताया गया कि अनुराधा (24) ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। इसे लेकर उसका कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। सोमवार रात दबंगों ने उससे मारपीट की। उसके पति रामा अहिरवार ने नागौद पुलिस से की शिकायत में हनुमान प्रसाद उपाध्याय (56), रविशंकर उपाध्याय (55), चुन्नू उर्फ आनंद उपाध्याय (33) व मुन्नू उर्फ सुलक्षण उपाध्याय (35) के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की है। मौत से पहले अनुराधा ने भी उक्त लोगों का नाम लिया था।

पूर्व कुलपति बृजकिशोर कुठियाला फरार घोषित

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश के भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. बृजकिशोर कुठियाला को अदालत ने फरार घोषित कर दिया है। उन्हें 31 जुलाई तक पेश होने की समयसीमा दी गई है। अदालत ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) को कुठियाला के हरियाणा में उच्च शिक्षा कौंसिल दफ्तर, सरकारी आवास व हिमाचल प्रदेश के प्रगपुरा पैतृक निवास पर नोटिस चस्पा करने के आदेश दिए हैं।

ईओडब्ल्यू में प्रो. कुठियाला सहित 20 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है। इस मामले में कुठियाला के बयान लेने के लिए ईओडब्ल्यू करीब दो महीने से प्रयास कर रहा था। ईओडब्ल्यू ने कुठियाला को पहला पत्र 17 मई को लिखा था, मगर कुठियाला तभी से पूछताछ से बच रहे हैं। उस समय कुठियाला ने रेल या हवाई टिकट नहीं मिलने का कारण बताते हुए आठ जून तक आने में असमर्थता जताई थी। फिर उन्होंने 11 जून को ईओडब्ल्यू को पत्र लिखकर 27 जून के बाद की कोई तारीख मांगी थी। तब इसमें कारण बताया था कि उनकी पूर्व निर्धारित बैठकों के कारण इसके पहले वे भोपाल नहीं आ सकते। उधर, जब ईओडब्ल्यू ने कुठियाला के खिलाफ फरार अपराधी घोषित कराने के लिए सीआरपीसी की धारा 82 की कार्रवाई शुरू की और जिला अदालत में आवेदन लगाया तो फिर उन्होंने 15 जुलाई को महानिदेशक ईओडब्ल्यू को पत्र भेजा। इसमें उन्होंने 18 जुलाई तक का समय मांगा और इसके बाद खुद पेश होने की बात कही।

हरियाणा उच्च शिक्षा कौंसिल दफ्तर, सरकारी आवास और हिमाचल प्रदेश के प्रगपुरा में नोटिस चस्पा करेगा ईओडब्ल्यू

प्रो. बृजकिशोर कुठियाला फाइल फोटो

देखते ही देखते इंटरनेट सनसनी बन गई रुद्राक्षी

जेएनएन, नई दिल्ली

मंगलवार को जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यालय में आई नन्हीं रुद्राक्षी के साथ अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं, लोग इसे देखने उमड़ पड़े। देखते ही देखते रुद्राक्षी इंटरनेट सनसनी बन गई। कुछ ही देर में यह तस्वीर इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी की सबसे ज्यादा देखी गई तस्वीरों में शुमार हो गई। इसे 25 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया। रुद्राक्षी भाजपा के राज्यसभा सदस्य सत्य नारायण जटिया की आठ माह की पोती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी सत्य नारायण जटिया अपने बेटे, बहू और पोती के साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे।

'संसद भवन में एक खास दोस्त मिलने आया' के कैप्शन के साथ पीएम मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीर आते ही लोगों ने बच्ची की पहचान को लेकर तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए थे। आलोचक और समर्थक सब अपनी-अपनी तरह से पोस्ट करने में जुटे थे। इन टिप्पणियों के बीच भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लिखा, 'भविष्य सुरक्षित हाथों में है।' जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कश्मीर मसले पर मध्यस्थता को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद संसद में चल रहे गतिरोध से इस तस्वीर को जोड़ा। उन्होंने लिखा, 'बहुत प्यारी तस्वीर। जब विपक्षी पार्टियां ट्रंप मामले पर प्रधानमंत्री से सफाई मांगने का हल्ला मचा रही थीं, उस समय यह तस्वीर पोस्ट करके पीएम ने बता दिया कि विपक्षियों की मांग के बारे में वह क्या सोचते हैं।' इंस्टाग्राम पर मोदी के 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं, जबकि वह किसी को फॉलो नहीं करते।

पीएम मोदी ने अपने कार्यालय आई नन्हीं बच्ची के साथ पोस्ट की थी तस्वीर

फोटोशॉप का भी दिखा कमाल : बच्ची के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ कई यूजर्स ने अलग-अलग तरह से प्रयोग भी किया। कुछ यूजर्स ने बच्ची की जगह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल लगाकर तस्वीर पोस्ट की, तो कुछ लोगों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चेहरा लगाकर भी प्रयोग किया।

चिंताजनक

अब तक इस घाटी में खिले हैं लगभग 150 प्रजाति के ही फूल, बीते वर्षों में इन दिनों घाटी में रंगत बिखेरते थे 300 से अधिक प्रजाति के फूल

इस बार फूलों की घाटी में नहीं पहले जैसी रंगत

रणजीत सिंह रावत, जोशीमठ (चमोली)

विश्व धरोहर फूलों की घाटी में अब तक वह फूल बेहद कम खिले हैं, जिनसे इन दिनों घाटी गुलजार रहा करती थी।

यह ग्लोबल वार्मिंग का असर है या शीतकाल के दौरान हुई भारी बर्फबारी की परिणति, कारण जो भी हों, लेकिन इस साल विश्व धरोहर फूलों की घाटी में बीते वर्षों जैसी रंगत नजर नहीं आ रही। अब तक घाटी में वह फूल बेहद कम खिले हैं, जिनसे इन दिनों घाटी गुलजार रहा करती थी। इससे घाटी के दीदार को पहुंचने वाले पर्यटक भी निराश हैं।

चमोली जिले में समुद्रतल से 12995 फीट की ऊंचाई पर 87.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली फूलों की घाटी में 500 से अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं। लेकिन, अभी तक घाटी में लगभग 150 प्रजाति के फूल ही नजर आ रहे हैं। जबकि, बीते वर्षों में इन दिनों 300 से अधिक प्रजाति के फूल घाटी में खिले रहते थे। फूलों की घाटी वन प्रभाग इस साल हुई औसत से कम बारिश और शीतकाल के दौरान हुई भारी बर्फबारी को इसकी मुख्य वजह मान रहा है।

वन क्षेत्राधिकारी बृजमोहन भारती घाटी बताते हैं कि अभी भी टिपरा समेत अन्य ग्लेशियर पॉइंट पर भारी मात्रा में बर्फ मौजूद है। यह बर्फ जैसे-जैसे पिघल रही है, वैसे-वैसे फूल भी अपनी छटा बिखेर रहे हैं। उम्मीद है कि 15 अगस्त तक यहां 300 से अधिक प्रजाति के फूल नजर आने लगेंगे। भारती के अनुसार अत्याधिक बर्फ और कम बारिश की वजह से इस साल फूलों के खिलने में ज्यादा वक्त लग रहा है। लेकिन, जैसे-जैसे घाटी में फूलों की संख्या बढ़ रही है, पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। घाटी के जानकार भरत सिंह चौहान भी कम वर्षा और अत्याधिक बर्फबारी को ही इस बदलाव का कारण मानते हैं।

प्रकृति में ऐसे बदलाव होना सामान्य बात: राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग में वनस्पति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. विश्वदीप भट्ट ने बताया कि वे सप्ताहभर पूर्व ही घाटी की सैर कर लौटे हैं। लगता है कि घाटी की मिट्टी में अभी फूल खिलने के अनुकूल स्थितियां नहीं बन पाई हैं। हालांकि, इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नियत अंतराल पर प्रकृति में ऐसे बदलाव आते रहते हैं। डॉ. भट्ट के अनुसार देर से ही सही, लेकिन धीरे-धीरे घाटी अपने पुरानी रंगत में आ जाएगी।

दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर हरियाणा ने उठाया सवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

हरियाणा और दिल्ली के बीच लंबे समय से चल रहे पानी बंटवारे के विवाद पर हरियाणा सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर ही सवाल उठाया है। हरियाणा सरकार ने मुख्य पीठ के समक्ष शपथ पत्र दाखिल कर कहा है यमुना से पानी के बंटवारे के विवाद पर सुनवाई करना दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। शपथ पत्र में यहां तक कहा गया कि मामले में आगे सुनवाई शुरू करने से पहले अधिकार क्षेत्र पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में भी दिल्ली हाई कोर्ट नाकाम रहा।

मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष दाखिल शपथ पत्र में हरियाणा सरकार ने दलील दी कि दो राज्यों के बीच पानी के विवाद पर फैसला करने के लिए अपर रिवर यमुना बोर्ड (यूआरवाईबी) ही उपयुक्त संस्था है। याचिकाकर्ता एसबी त्रिपाठी की जनहित याचिका पर यह जवाब दाखिल करते हुए हरियाणा सरकार ने मांग की कि वह अधिकार क्षेत्र के मामले पर प्राथमिकता पर फैसला करने को कहा।

हरियाणा सरकार ने इसके साथ ही हाई कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट पर भी आपत्ति जताई। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट से मांग की कि यमुना में बड़े पैमाने पर खोदाई का दावा करने वाली कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करे। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा था कि खोदाई से पानी का बहाव तो नहीं रुक रहा है, लेकिन इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हरियाणा सरकार ने कहा कि यह रिपोर्ट सिर्फ एक निरीक्षण करने के बाद दाखिल की गई और दाखिल करने से पहले उनके साथ साझा भी नहीं की गई। हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड के उस आवेदन पर कमेटी गठित की थी। जिसमें जल बोर्ड ने दावा किया था कि कैनाल में बांध बनाए गए हैं और इसके कारण राष्ट्रीय राजधानी की जरूरत के हिसाब से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है।

हरियाणा सरकार का दावा दिल्ली को मिल रहा पूरा पानी : कमेटी की रिपोर्ट के अलावा हरियाणा सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के पानी की आपूर्ति कम होने के दावे का विरोध किया। हरियाणा सरकार ने दावा किया कि पानी की ज्यादा मांग के दौरान भी 30 जून के आखिरी तक यमुना से दिल्ली को की गई पानी की आपूर्ति उत्कृष्ट रही थी। शपथ पत्र में यह भी दावा किया गया कि दिल्ली को उसकी जरूरत से दोगुना पानी उपलब्ध कराया गया है और कैनाल में बने बांध से राष्ट्रीय राजधानी के पानी के प्रवाह पर असर नहीं पड़ा। हरियाणा सरकार ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार बेवजह ही जनहित याचिका का सहारा लेकर दिल्ली में पानी की आपूर्ति के मामले को उठा रहा है, जबकि इस पर फैसला लेने का दिल्ली हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है।